



The ACHIEVERS

IAS ACADEMY
PATNA

Daily NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Monday, July 13, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- भारत और न्यूजीलैंड ने प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
- केंद्र ने उच्च अल्कोहल वाली दवाओं के विनियमन को मजबूत करने के लिए औषधि नियमों में संशोधन किया
- झारखंड ने एआई-आधारित शासन और नवाचार के लिए एआई नीति 2026-2031 का मसौदा पेश किया
- दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पैंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य
- फेडरल बैंक को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निवेश-ग्रेड रेटिंग प्राप्त हुई
- भारत और किर्गिस्तान ने मानस और महाभारत सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया
- दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम पहल ने ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार जीता
- एआईएसएचई रिपोर्ट 2023-24 से पता चलता है कि महिला उच्च शिक्षा नामांकन सातवें वर्ष में सबसे आगे है
- सौरव गांगुली को क्रिकेट की उत्कृष्टता के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया
- उत्तर प्रदेश ने किसानों की सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए निशुल्क बोरिंग योजना का विस्तार किया

भारत और न्यूजीलैंड ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए



- ऑकलैंड में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन को कवर करने वाले पांच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इन समझौतों का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए रणनीतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है।
- यह यात्रा लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है।

पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर:

रक्षा सहयोग:

- रक्षा मंत्रालय (भारत) और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच समझौता ज्ञापन।
- समुद्री सहयोग, रक्षा आदान-प्रदान और हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
- पशुपालन और डेयरी: पशुधन प्रबंधन, डेयरी अनुसंधान, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान में सहयोग।
- पर्यटन सहयोग: पर्यटन को बढ़ावा देना, आगंतुकों का आदान-प्रदान और पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग।
- खेलों पर संयुक्त कार्य योजना: खेल विकास, एथलीट आदान-प्रदान, कोचिंग और खेल प्रशासन में सहयोग।
- आपदा प्रबंधन: आपदा तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, जोखिम में कमी और लचीलापन निर्माण में सहयोग।

भारत-न्यूजीलैंड संबंध:

- राजनयिक संबंध: 1952 में स्थापित।
- रणनीतिक साझेदारी: प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।
- भारत के प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है।

दोनों देश निम्नलिखित में सहयोग करते हैं:

- हिंद-प्रशांत सुरक्षा
- व्यापार और निवेश
- कृषि और डेयरी
- पढ़ाई
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- खेल
- जलवायु और आपदा लचीलापन
- रक्षा सहयोग

न्यूजीलैंड के बारे में:

- राजधानी: वेलिंगटन।
- सबसे बड़ा शहर: ऑकलैंड।
- मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर (NZD)।
- संसद: एकसदनीय संसद (प्रतिनिधि सभा)।
- पड़ोसी जल निकाय: तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर।

अन्य हालिया द्विपक्षीय घटनाक्रम:

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA): द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): न्यूजीलैंड ने ISA फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है।
- सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था: व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सीमा शुल्क सहयोग में सुधार के लिए हस्ताक्षर।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- देश: भारत और न्यूजीलैंड।
- स्थान: ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
- नेता: नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन।
- समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर: पांच।
- प्रमुख क्षेत्र: रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन।
- रक्षा फोकस: समुद्री सहयोग और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा।
- राजनयिक संबंध: 1952।

- भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा: लगभग 40 साल - न्यूजीलैंड की राजधानी: वेलिंगटन।	मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर (NZD)।
--	--

केंद्र ने उच्च अल्कोहल युक्त दवा फॉर्मूलेशन के विनियमन को मजबूत करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया



- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने एथिल अल्कोहल के उच्च स्तर वाले औषधीय फार्मूलेशनों के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए औषध नियम, 1945 में संशोधन किया है।
- संशोधन के तहत, 30 एमएल से अधिक पैक आकार में 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल वाले औषधीय फॉर्मूलेशन को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची के तहत छूट नहीं दी जाएगी।
- इन उत्पादों को अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होगी और इन्हें अनुसूची एच-1 के तहत लाया गया है, जिससे वे सख्त निगरानी और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के साथ केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं बन गए हैं। इस कदम का उद्देश्य वास्तविक चिकित्सीय उपयोग के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए ऐसे फॉर्मूलेशन के दुरुपयोग को रोकना है।

मुख्य संशोधन:

अनुसूची K छूट की वापसी:

- 30 एमएल से अधिक के पैकों में 12% से अधिक वी/वी एथिल अल्कोहल वाले औषधीय फार्मूलेशनों को अनुसूची K के तहत लाइसेंसिंग छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

अनुसूची H1 के तहत समावेश:

- इन फार्मूलेशनों को अब अनुसूची एच-1 औषधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- केवल एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) के पर्चे पर बिक्री।
- फार्मेशियों को एक अलग बिक्री रजिस्टर बनाए रखना चाहिए और रिकॉर्ड संरक्षित करना चाहिए।

लाइसेंसिंग आवश्यकता:

- निर्माताओं और विक्रेताओं को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

वस्तुनिष्ठ:

- नशीले पदार्थों के रूप में उच्च अल्कोहल युक्त औषधीय योगों के दुरुपयोग को रोकें।
- सुरक्षित और विनियमित चिकित्सीय उपयोग सुनिश्चित करें।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- कुछ औषधीय तैयारी जैसे इलायची का टिचर, अदरक का टिचर और अन्य सुगंधित टिचर में 80-90% वी/वी एथिल अल्कोहल होता है।
- इन उत्पादों को पहले अनुसूची K के तहत छूट दी गई थी, जिससे वे दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो गए थे।
- कई राज्य सरकारों ने नशे के लिए ऐसे उत्पादों के दुरुपयोग और विपथन की सूचना दी है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940:

- भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून।
- दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- केंद्र सरकार को औषधि नियम, 1945 बनाने का अधिकार देता है।

औषधि नियम, 1945:

- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत तैयार किया गया।
- निम्नलिखित से संबंधित नियम निर्धारित करें:

- लाइसेंसिंग - उत्पादन करना - भंडार - वितरण - बिक्री - लेबलिंग - दवाओं के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकताएं।
--

अनुसूची K के बारे में:

- निर्दिष्ट दवाओं और औषधीय तैयारियों को परिभाषित शर्तों के तहत कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों से छूट दी गई है।
- नवीनतम संशोधन निर्दिष्ट उच्च अल्कोहल युक्त फॉर्मूलेशन के लिए इस छूट को हटा देता है।

अनुसूची H1 के बारे में:

- दुरुपयोग के उच्च जोखिम वाली दवाओं को विनियमित करने के लिए पेश किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ:

- केवल डॉक्टर के पर्चे पर बिक्री।
- फार्मेशियों द्वारा बिक्री रिकॉर्ड का अनिवार्य रखरखाव।
- दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है और दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)।
• कानून: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
• नियमों में संशोधन: औषधि नियम, 1945।
• अल्कोहल थ्रेशोल्ड: 12% से अधिक v/v एथिल अल्कोहल।
• पैक का आकार कवर किया गया: 30 एमएल से अधिक।
• अनुसूची प्रभावित: अनुसूची K (लाइसेंसिंग छूट वापस ले ली गई)।
• नया वर्गीकरण: अनुसूची H1।
• प्रिस्क्रिप्शन आवश्यकता: एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) द्वारा अनिवार्य नुस्खे।
• उद्देश्य: चिकित्सीय उपयोग सुनिश्चित करते हुए उच्च अल्कोहल युक्त औषधीय योगों के दुरुपयोग को रोकना।

झारखंड ने एआई-संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एआई नीति 2026-2031 का मसौदा जारी किया



- झारखंड सरकार ने झारखंड एआई नीति 2026-2031 के मसौदे का अनावरण किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में एकीकृत करने के लिए अगले पांच वर्षों में 1,150 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
- नीति का उद्देश्य एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सरकारी विभागों में एआई अपनाने में तेजी लाना है।
- प्रमुख फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खनन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन शामिल हैं।
- यह नीति नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान प्रस्तुत की गई थी।

- एआई-तैयार डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करें।
- दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन में सुधार करें।
- एआई नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
- एक नैतिक और जिम्मेदार एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

• स्वास्थ्य देखभाल
• कृषि
• खनन-उद्योग
• पढ़ाई
• आपदा प्रबंधन
• पर्यावरण प्रबंधन
• शहरी शासन
• सार्वजनिक सेवा वितरण

एआई नीति 2026-2031 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं:

- निवेश: पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ का प्रस्तावित निवेश।

उद्देश्य:

फ्लैगशिप डिजिटल पहल:

- सभी विभागों में डेटा-संचालित शासन और एआई-संचालित निर्णय लेने को सक्षम करने के लिए मुख्यमंत्री का डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम-डीआईपी)।

विजन और लक्ष्य:

- झारखंड को एक अग्रणी एआई-सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करें।
- एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करें।
- एआई नवाचार केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना।
- एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षाविदों में एआई अपनाने को बढ़ावा देना।
- एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

इंडियाएआई मिशन के बारे में:

- द्वारा लॉन्च किया गया: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।

वस्तुनिष्ठ:

- स्वदेशी एआई क्षमताओं का निर्माण करें।
- एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें।
- एआई स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना।
- एआई कौशल और डेटासेट बढ़ाएँ।
- जिम्मेदार और नैतिक एआई अपनाने को प्रोत्साहित करें।
- वैश्विक एआई लीडर बनने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:

- शुरू किया गया: 1 जुलाई 2015।
- मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)।

विजन:

- एक मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा।
- मांग पर शासन और सेवाएँ।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।
- शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली कार्ड' अनिवार्य



- दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

एआई अनुप्रयोगों में शामिल हैं:

- नीति निर्माण के लिए भविष्य कहनेवाला विश्लेषण।
- स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल और रोग निगरानी।
- सटीक कृषि।
- आपदा की भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया।
- यातायात और शहरी प्रबंधन।
- डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण।
- धोखाधड़ी का पता लगाना और शिकायत निवारण।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- राज्य: झारखंड।
- नीति: झारखंड एआई नीति 2026-2031 का मसौदा।
- निवेश: ₹1,150 करोड़।
- अवधि: पांच वर्ष (2026-2031)।
- उद्देश्य: एआई-संचालित शासन और डिजिटल परिवर्तन।
- फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म: मुख्यमंत्री का डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP)।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र: स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, खनन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और शासन।
- संबंधित राष्ट्रीय पहल: इंडियाएआई मिशन।
- संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम: डिजिटल इंडिया।
- नोडल मंत्रालय (इंडियाएआई और डिजिटल इंडिया): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)।

- नई प्रणाली 1 अगस्त 2026 से लागू होगी, जो 2019 में शुरू की गई मौजूदा पेपर-आधारित गुलाबी टिकट प्रणाली की जगह लेगी।
- महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए बसों में चढ़ते समय एनसीएमसी-सक्षम गुलाबी सहेली कार्ड ले जाना होगा और टैप करना होगा।
- इस पहल का उद्देश्य योजना को डिजिटल बनाना, पारदर्शिता में सुधार करना, दुरुपयोग को रोकना और लाभार्थी सत्यापन को सुव्यवस्थित करना है।

प्रयुक्त तकनीक:

- एनसीएमसी-सक्षम (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड।

- यात्रियों को बोर्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) पर कार्ड को टैप करना होगा।

उद्देश्य:

- पेपर पिक टिकट बदलें।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करें और धोखाधड़ी कम करें।
- लाभार्थी सत्यापन को डिजिटाइज करें।
- सार्वजनिक परिवहन सेवा वितरण में दक्षता में सुधार करना।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के बारे में:

- लोकप्रिय रूप से "एक राष्ट्र, एक कार्ड" के रूप में जाना जाता है।
- सार्वजनिक परिवहन और खुदरा क्षेत्र में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और NPCI के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है।
- रुपे भुगतान प्रणाली के आधार पर।

इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है:

- मेट्रो रेल
- बसें
- पार्किंग
- टोल भुगतान
- खुदरा खरीदारी
- एटीएम निकासी (जहां लागू हो)।

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के बारे में:

- स्थापित: 1971.
- अध्यक्ष: निहारिका राय,
- प्रबंध निदेशक: जितेंद्र यादव
- प्रशासनिक नियंत्रण: दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार।
- भारत की सबसे बड़ी शहरी बस परिवहन प्रणालियों में से एक का संचालन करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली।
- योजना: गुलाबी सहेली स्मार्ट कार्ड।
- से अनिवार्य: 1 अगस्त 2026।
- लाभार्थी: 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और लड़कियां जो दिल्ली के निवासी हैं।
- परिवहन कवर: डीटीसी और क्लस्टर बसें।
- प्रौद्योगिकी: नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)।
- उद्देश्य: पेपर पिक टिकटों को डिजिटल स्मार्ट कार्ड से बदलें।
- उद्देश्य: महिलाओं के लिए पारदर्शी, कुशल और धोखाधड़ी प्रतिरोधी मुफ्त बस यात्रा।
- संबंधित पहल: एक राष्ट्र, एक कार्ड (एनसीएमसी)।
- NCMC के लिए नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)।

फेडरल बैंक को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स से पहली अंतर्राष्ट्रीय निवेश-ग्रेड जारीकर्ता रेटिंग प्राप्त हुई



- फेडरल बैंक को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय निवेश-ग्रेड जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश-ग्रेड रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक बन गया है।

- एसएंडपी ने बैंक को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी-' दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग और 'ए-3' अल्पकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग प्रदान की।
- रेटिंग बैंक की मजबूत वित्तीय प्रोफाइल, अच्छी परिसंपत्ति गुणवत्ता, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और पर्याप्त पूंजीकरण को दर्शाती है।
- निवेश-ग्रेड रेटिंग से फेडरल बैंक की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ने, निवेशकों का विश्वास मजबूत होने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है।

रेटिंग विवरण:

- रेटिंग एजेंसी: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स।
- दीर्घकालिक रेटिंग: बीबीबी- (निवेश ग्रेड)।

● अल्पकालिक रेटिंग: ए-3।

● आउटलुक: स्थिर।

निवेश-ग्रेड रेटिंग के बारे में:

- निवेश-ग्रेड रेटिंग डिफॉल्ट के अपेक्षाकृत कम जोखिम का संकेत देती है।
- एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग के तहत, बीबीबी- सबसे कम निवेश-ग्रेड दीर्घकालिक रेटिंग है।
- BB+ और उससे नीचे की रेटिंग को सट्टा (गैर-निवेश ग्रेड या जंक स्टेटस) माना जाता है।
- क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को बैंकों, कंपनियों और सरकारों की पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने में मदद करती है।

S&P ग्लोबल रेटिंग्स के बारे में:

- दुनिया की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- सरकारों, वित्तीय संस्थानों और निगमों की साख का स्वतंत्र आकलन प्रदान करता है।
- तीन प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं:

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग:

- मूडीज रेटिंग्स
- फिच रेटिंग

फेडरल बैंक के बारे में:

● स्थापित: 1931.

● मुख्यालय: अलुवा, केरला।

● एमडी और सीईओ: केवीएस मणियान

● प्रकार: निजी क्षेत्र का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

● पूरे भारत में खुदरा, कॉर्पोरेट, एसएमई, एनआरआई और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

● बैंक: फेडरल बैंक।

● रेटिंग एजेंसी: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स।

● दीर्घकालिक रेटिंग: बीबीबी-।

● अल्पकालिक रेटिंग: ए-3।

● आउटलुक: स्थिर।

● महत्व: फेडरल बैंक के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय निवेश-ग्रेड जारीकर्ता रेटिंग।

● न्यूनतम निवेश ग्रेड (एस एंड पी): बीबीबी-.

● निवेश ग्रेड से नीचे: बीबी+ और नीचे।

● फेडरल बैंक का मुख्यालय: अलुवा, केरला।

● स्थापित: 1931.

भारत और किर्गिस्तान ने 'मानस और महाभारत' सभ्यता अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया



- भारत और किर्गिस्तान ने दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से किर्गिस्तान के बिश्केक में अंतराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र "मानस और महाभारत" का उद्घाटन किया है।

● सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएसआईआर), नई दिल्ली और मानस नेशनल एकेडमी, किर्गिस्तान के बीच सहयोग के माध्यम से केंद्र की स्थापना की गई है।

● इस पहल का उद्देश्य भारतीय महाकाव्य महाभारत और किर्गिज राष्ट्रीय महाकाव्य मानस पर तुलनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, साथ ही लोगों से लोगों के बीच संबंधों और सांस्कृतिक कूटनीति को गहरा करना है। उद्घाटन के दौरान, किर्गिज महाकाव्य "मानस" का पहला हिंदी अनुवाद भी जारी किया गया।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज के बारे में:

● स्थान: बिश्केक, किर्गिस्तान।

● सहयोगी संस्थान: सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएसआईआर), नई दिल्ली और मानस नेशनल एकेडमी, किर्गिस्तान।

● फोकस क्षेत्र:
● महाभारत और मानस महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन।
● सभ्यतागत इतिहास और सांस्कृतिक विरासत।
● अंतरसांस्कृतिक संवाद और मानवीय कूटनीति।
● अकादमिक सहयोग और शोधकर्ता प्रशिक्षण।

महाकाव्य "मानस" के बारे में:

- किर्गिस्तान का राष्ट्रीय महाकाव्य और दुनिया के सबसे लंबे मौखिक महाकाव्यों में से एक।
- किर्गिज लोगों के महान संस्थापक और एकीकरण करने वाले मानस के जीवन और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है।
- यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- परंपरागत रूप से मानस (पारंपरिक महाकाव्य कथाकार) द्वारा मौखिक पाठ के माध्यम से संरक्षित किया जाता है।

महाभारत के बारे में:

- भारत के दो महान संस्कृत महाकाव्यों में से एक, दूसरा रामायण है।
- पारंपरिक रूप से महर्षि वेद व्यास को श्रेय दिया जाता है।
- इसमें 100,000 से अधिक छंद शामिल हैं, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक बनाते हैं।
- इसमें भगवद गीता, हिंदू धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ शामिल है।

किर्गिस्तान के बारे में:

● राजधानी: बिश्केक।
● मुद्रा: किर्गिस्तान सोम (KGS)।
● राष्ट्रपति: सदिर जापरोव।
● क्षेत्र: मध्य एशिया।
● सीमाएँ: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन।
● भारत-किर्गिस्तान संबंध: दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य हैं और संस्कृति, शिक्षा, रक्षा और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।

परीक्षा फोकस बिंदु:

● शामिल देश: भारत और किर्गिस्तान।
● केंद्र का शुभारंभ: इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज "मानस एंड महाभारत"।
● स्थान: बिश्केक, किर्गिस्तान।
● भारतीय भागीदार: सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएसआईआर), नई दिल्ली।
● किर्गिज पार्टनर: मानस नेशनल एकेडमी।
● प्रमुख उद्देश्य: तुलनात्मक सभ्यतागत अध्ययन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना।
● अतिरिक्त उपलब्धि: किर्गिज महाकाव्य मानस का पहला हिंदी अनुवाद जारी किया गया।
● यूनेस्को लिंक: मानस महाकाव्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है।

दूरसंचार विभाग के समृद्ध ग्राम ने ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2026 जीता



- दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपनी प्रमुख पहल "समृद्ध ग्राम: इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल इनेबल्ड बाय भारतनेट" के लिए एक्शन लाइन C6 – इनेबलिंग एनवायरनमेंट के तहत सूचना समाज (WSIS) पुरस्कार 2026 पर प्रतिष्ठित विश्व शिखर सम्मेलन जीता है।

- यह पुरस्कार स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित डब्ल्यूएसआईएस फोरम 2026 के दौरान प्रदान किया गया, जिसमें ग्रामीण सेवा वितरण को बदलने के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अभिनव उपयोग को मान्यता दी गई।
- यह पहल गांवों में समृद्धि केंद्रों को वन-स्टॉप डिजिटल सेवा केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए भारतनेट का लाभ उठाती है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस, कौशल और ई-कॉमर्स सेवाओं तक एकीकृत पहुंच प्रदान करती है। यह मान्यता समावेशी डिजिटल शासन और ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालती है।

प्रयुक्त तकनीक:

- भारतनेट हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क।

- एकीकृत फिजिटल (भौतिक + डिजिटल) सेवा वितरण मॉडल।
- डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में ग्राम स्तरीय समृद्धि केंद्र।
- एफटीटीएच (फाइबर-टू-द-होम) कनेक्टिविटी और सार्वजनिक वाई-फाई।

उद्देश्य:

- ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटना।
- ग्रामीण स्तर पर नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करना।
- डिजिटल समावेशन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना।

समृद्ध ग्राम पहल के बारे में:

- दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
- भारतनेट ब्रॉडबैंड बैकबोन पर निर्मिता।
- भौतिक सेवा केंद्रों के साथ डिजिटल प्लेटफार्मों को जोड़कर एक फिजिटल मॉडल लागू करता है।

सेवाएं प्रदान करता है जैसे:

- टेलीमेडिसिन
- डिजिटल शिक्षा
- स्मार्ट कृषि
- ई-गवर्नेंस
- डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन
- कौशल विकास
- ई-कामर्स
- सार्वजनिक वाई-फाई और ब्रॉडबैंड का उपयोग।

भारतनेट के बारे में:

- भारत सरकार की प्रमुख ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना।
- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कार्यान्वित (अब बीएसएनएल के साथ विलय)।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है।
- इसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता का समर्थन करता है।

WSIS पुरस्कारों के बारे में:

- सूचना समाज (डब्ल्यूएसआईएस) प्रक्रिया पर विश्व शिखर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा आयोजित किया गया।
- सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान देने वाली अभिनव आईसीटी-आधारित परियोजनाओं को मान्यता देता है।
- WSIS फोरम 2026 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

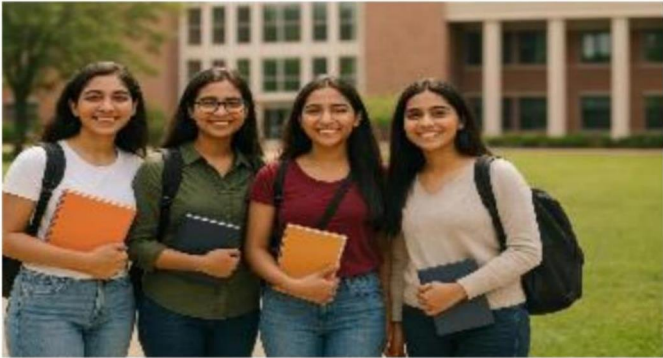
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में:

- स्थापित: 1865।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- महासचिव: डोरन बोगडान-मार्टिन
- स्थिति: संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी (1947 से)।
- दूरसंचार और आईसीटी में वैश्विक मानकों के लिए जिम्मेदार।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- मंत्रालय: संचार मंत्रालय।
- कार्यान्वयन विभाग: दूरसंचार विभाग (डीओटी)।
- पहल: समृद्ध ग्राम - एकीकृत फिजिटल सेवा वितरण मॉडल।
- पुरस्कार: WSIS पुरस्कार 2026।
- पुरस्कार श्रेणी: एक्शन लाइन C6 - पर्यावरण को सक्षम करना।
- आयोजन निकाय: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)।
- स्थान: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- प्रौद्योगिकी रीढ़ की हड्डी: भारतनेट।
- ग्राम सेवा केंद्र: समृद्धि केंद्र।
- उद्देश्य: एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन।
- आईटीयू मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- आईटीयू की स्थापना: 1865।

एआईएसएचई 2023-24: उच्च शिक्षा में महिला नामांकन लगातार सातवें वर्ष पुरुष नामांकन से अधिक



- शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2023-24 जारी किया है, जिसमें भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि महिला नामांकन लगातार सातवें वर्ष पुरुष नामांकन से अधिक हो गया है, जिसमें महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) पुरुषों के लिए 28.9% की तुलना में 31.2% तक पहुंच गया है।
- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन रिकॉर्ड 4.50 करोड़ छात्रों तक पहुंच गया है, जबकि महिला नामांकन बढ़कर 2.24 करोड़ हो गया है, जो 2014-15 के बाद से 42.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।
- निष्कर्ष देश भर में लैंगिक समानता में सुधार और उच्च शिक्षा तक अधिक पहुंच को दर्शाते हैं।

AISHE (उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण) के बारे में:

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2010-11 में लॉन्च किया गया।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से डेटा एकत्र करता है।

इस पर आंकड़े प्रदान करता है:

• छात्र नामांकन
• सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)
• संकाय
• अवसरचना
• अनुसंधान
• वित्तीय संकेतक
• लिंग और सामाजिक श्रेणी-वार भागीदारी।

सकल नामांकन अनुपात (GER) के बारे में:

- जीईआर उच्च शिक्षा (18-23 वर्ष आयु वर्ग) में नामांकित छात्रों का प्रतिशत है, जो उसी आयु वर्ग की कुल आबादी की तुलना में है।
- एक उच्च जीईआर उच्च शिक्षा तक अधिक पहुंच को इंगित करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बारे में:

- 2020 में स्वीकृत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह।
- भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने का उद्देश्य:**

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच।
- बहु-विषयक उच्च शिक्षा।
- 2035 तक जीईआर को बढ़ाकर 50% कर दिया गया।
- राष्‍ट्रीय अनुसंधान संस्‍थान (एनआरएफ) के माध्‍यम से अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा का अधिक उपयोग।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- सर्वेक्षण: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2023-24।
- द्वारा जारी: शिक्षा मंत्रालय।
- द्वारा संचालित: उच्च शिक्षा विभाग।
- कुल नामांकन: 4.50 करोड़।
- महिला नामांकन: 2.24 करोड़।
- महिला जीईआर: 31.2%।
- पुरुष जीईआर: 28.9%।
- कुल मिलाकर जीईआर: 30.0%।
- महिला नामांकन वृद्धि (2014-15 से): 42.2%।
- कुल नामांकन वृद्धि (2014-15 से): 31.5%।
- एनईपी 2020 जीईआर लक्ष्य: 2035 तक 50 प्रतिशत।
- एआईएसएचई का शुभारंभ: 2010-11।
- प्रमुख उपलब्धि: लगातार सातवें वर्ष महिला नामांकन पुरुष नामांकन की तुलना में अधिक रहा है।



- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो यह सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं।
- यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गांगुली के उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम के उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व का जश्न मनाता है।
- भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाने वाले गांगुली ने मैच फिक्सिंग संकट के बाद भारतीय क्रिकेट के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, युवा प्रतिभाओं को निखारने और भारत को एक मजबूत विदेशी प्रतिद्वंद्वी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ICC हॉल ऑफ फेम के बारे में:

- अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा 2009 में अपने शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
- महान क्रिकेटरों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और खेल पर स्थायी प्रभाव के लिए पहचानता है।
- आईसीसी द्वारा समय-समय पर नए शामिल लोगों की घोषणा की जाती है।
- हॉल ऑफ फेम में दुनिया भर के पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर शामिल हैं।

सौरव गांगुली के बारे में:

- फूल का नाम सौरव चंडीदास गांगुली है।
- उपनाम: दादा; कोलकाता के राजकुमार।
- जन्म: 8 जुलाई 1972, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
- बल्लेबाजी शैली: बाएं हाथ का बल्लेबाज।
- भूमिका: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान।
- पूर्व पद: अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) (2019-2022)।

उत्तर प्रदेश ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई को मजबूत करने के लिए निशुल्क बोरिंग योजना का विस्तार किया

- उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई कवरेज में सुधार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से पात्र किसानों को मुफ्त बोरवेल ड्रिलिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए निशुल्क बोरिंग योजना (फ्री बोरिंग स्कीम) के कार्यान्वयन को जारी रखा है।

- वर्तमान भूमिका: अध्यक्ष, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति।

सौरव गांगुली की प्रमुख उपलब्धियां:

- उन्होंने 1996 में लॉर्ड्स में शतक के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था।
- 2003 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया।
- एक निडर और प्रतिस्पर्धी भारतीय टीम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सभी प्रारूपों में 18,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए।
- भारत के सबसे सफल वनडे कप्तानों में से एक।

अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बारे में:

- स्थापना: 1909 (इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में)।
- मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
- अध्यक्ष: जय शाह।
- भूमिका: क्रिकेट के खेल के लिए वैश्विक शासी निकाय।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- समाचार में व्यक्ति: सौरव गांगुली।
- पुरस्कार/सम्मान: आईसीसी हॉल ऑफ फेम।
- उपलब्धि: 12वें भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- आयोजन निकाय: अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)।
- आईसीसी हॉल ऑफ फेम लॉन्च: 2009।
- आईसीसी मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
- आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष: जय शाह।
- बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष: सौरव गांगुली (2019-2022)।
- आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष: सौरव गांगुली।
- विश्व कप उपलब्धि: भारत को 2003 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचाया।

- यह योजना मुख्य रूप से निजी नलकूपों की स्थापना की लागत को कम करके और विश्वसनीय सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करती है। यह उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग के

माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए राज्य के प्रयासों का समर्थन करता है।



फ़ायदे:

- पात्र किसानों को निजी नलकूपों के लिए निशुल्क बोरिंग (ड्रिलिंग) प्रदान करता है।
- निर्धारित मानदंडों के तहत पंप सेटों और एचडीपीई पाइपों के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।
- वर्षा सिंचित और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करता है।
- मानसूनी वर्षा पर निर्भरता कम करता है।
- फसल उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाता है।

उद्देश्य:

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई कवरेज का विस्तार करना।
- टिकाऊ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना।
- किसानों के लिए सिंचाई लागत कम करें।
- जहां संभव हो भूजल आधारित सिंचाई को मजबूत करना।
- ग्रामीण आजीविका और कृषि विकास का समर्थन करना।

वांछनीयता:

- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- कृषि भूमि के साथ एक छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए।
- आवेदक के पास संबंधित भूमि पर पहले से ही पर्याप्त सिंचाई की सुविधा नहीं होनी चाहिए।
- योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आथक रूप से कमजोर किसानों और पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वरीयता दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज:

- आधार कार्ड।
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज (खतौनी/खसरा)।
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।

- जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
- संबंधित राज्य पोर्टल/पीएम-किसान के तहत किसान पंजीकरण विवरण, जहां भी लागू हो।

निचुल्क बोरिंग योजना के बारे में:

- राज्य: उत्तर प्रदेश।
- कार्यान्वयन विभाग: लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- पात्र किसानों के लिए निजी नलकूपों की स्थापना के लिए निशुल्क बोरिंग की व्यवस्था करता है।
- कृषि के लिए सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं के विकास का समर्थन करता है।
- आवेदन लघु सिंचाई विभाग और उसके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के बारे में:

- निजी ट्यूबवेल, बोरवेल, तालाब और अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए स्थापित।
- भूजल आधारित सिंचाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राज्य में कृषि उत्पादकता और सूखे की लचीलापन बढ़ाने में योगदान देता है।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- लघु सिंचाई: 2,000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA) वाली सिंचाई परियोजनाओं को संदर्भित करता है।
- प्रमुख सिंचाई: 10,000 हेक्टेयर से अधिक सीसीए।
- मध्यम सिंचाई: 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच सीसीए।
- भारत में भूजल सिंचाई मुख्य रूप से ट्यूबवेल, कुओं और बोरवेल के माध्यम से की जाती है।
- उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सिंचित कृषि क्षेत्रों में से एक है, जहां नहरों, ट्यूबवेल और भूजल संसाधनों द्वारा समर्थित सिंचाई है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- योजना: निशुल्क बोरिंग योजना।
- राज्य: उत्तर प्रदेश।
- कार्यान्वयन विभाग: लघु सिंचाई विभाग।
- लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान।
- प्रमुख लाभ: निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बोरिंग और योजना के मानदंडों के अनुसार सिंचाई उपकरणों के लिए सहायता।

- उद्देश्य: सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना।
- आवेदन का तरीका: लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन।

- क्षेत्र: कृषि और सिंचाई।

लेट्स रिवाइज

- ❖ हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? **पांच।**
- ❖ उच्च अल्कोहल युक्त औषधीय योगों के विनियमन को मजबूत करने के लिए हाल ही में किन नियमों में संशोधन किया गया था? **औषधि नियम, 1945।**
- ❖ झारखंड ने अपनी मसौदा एआई नीति 2026-2031 के तहत कितने निवेश का प्रस्ताव दिया है? **₹1,150 करोड़**
- ❖ अगस्त 2026 से दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए कौन सा स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? **गुलाबी सहेली स्मार्ट कार्ड।**
- ❖ किस वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने फेडरल बैंक को अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय निवेश-ग्रेड जारीकर्ता रेटिंग प्रदान की? **एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स।**
- ❖ भारत और किर्गिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किए गए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज के फोकस में कौन से दो महाकाव्य हैं? **महाभारत (भारत) और मानस (किर्गिस्तान)।**
- ❖ दूरसंचार विभाग की किस प्रमुख पहल ने एक्शन लाइन C6 – सक्षम पर्यावरण के तहत WSIS पुरस्कार 2026 जीता? **समृद्ध ग्राम: भारतनेट द्वारा सक्षम एकीकृत डिजिटल सेवा वितरण मॉडल।**
- ❖ एआईएसएचई 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में भारत का महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्या था? **31.2%।**
- ❖ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? **सौरव गांगुली।**
- ❖ उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना सिंचाई में सुधार के लिए पात्र छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त बोरवेल ड्रिलिंग की सुविधा प्रदान करती है? **निशुल्क-बोरिंग योजना (निःशुल्क बोरिंग योजना)।**



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA